अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
1. आंध्र प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए फ्री जल आपूर्ति की व्यवस्था जारी रखना। फसल ऋण सुविधा देना जिसके तहत 3.75 लाख नए किसानों को फसल ऋण पर ब्याज राहत दी गई है। 	<ul style="list-style-type: none"> इंदिराम्मा के तहत और 1/3 गावों में पक्के घरों का निर्माण। 	<ul style="list-style-type: none"> दूरस्थ स्थानों में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 4 नए महाविद्यालयों, 5 कनिष्ठ महाविद्यालयों और 8 होस्टलों की स्थापना। ग्रामीण बच्चों के लिए स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 21वीं सदी के गुरुकुलमों की स्थापना। आईटीएस उद्योग में स्नातकों को लाभपूर्ण रोजगार मुहैया कराने के लिए सभी महाविद्यालयों तक जवाहर ज्ञान केंद्र की धारणा का विस्तार करना।
2. अरुणाचल प्रदेश		<ul style="list-style-type: none"> सरकार महिलाओं से संबंधित विशेष कल्याण कार्यक्रम लाएगी। 	
3. असम		<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों का पुनरुज्जीवन और सशक्तिकरण। गरीब और शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए दो नई योजनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे की कक्षा VI और कक्षा X के बीच की विद्यार्थी लड़कियों को साइकिल प्रदान करना। ग्रामीण आवास संबंधी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्रामीण आवास बोर्ड का गठन। आतंकवाद के शिकार लोगों के पारिवारिक सदस्यों के कल्याणार्थ आतंकवाद पीड़ितों के लिए कल्याण बोर्ड बनाना। 	<ul style="list-style-type: none"> किसानों को पॉवर टिलर, पॉवर थ्रेशर, हस्त दाब वाला छिड़काव यंत्र, भू-जांच किट आदि जैसे साधनों का वितरण। ट्रैक्टर वितरण और प्रत्येक जिले में उर्वरक बिक्री डेपो स्थापित करके कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देना। राज्य के विभिन्न जिलों में औषधीय और सुगंधित वाटिकाएं तथा नर्सरियां लगाना। 2007-08 के दौरान संवर्धित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम, शहरी बुनियादी संरचना विकास योजना जैसी नई जलापूर्ति योजनाएं शुरू करना। आठ नई प्रशिक्षण पाठशालाओं, पांच नए जिला अस्पतालों, पांच नए क्षेत्रीय निदान केंद्रों, तीन नए चिकित्सा महाविद्यालयों का गठन और प्रत्येक जिले में चिकित्सा की चल इकाइयों की स्थापना। गुवाहाटी में संपूर्ण सुविधाओं से युक्त नए आइटी पार्क का गठन।
4. बिहार	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के बुरी स्थिति वाले उद्योगों के पुनरुज्जीवन के लिए आधार निधि तैयार करना। मोटर वाहन कर में कटौती। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक पंचायत में "किसान-सलाहकार" नियुक्त करना। प्रत्येक जिले में "कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्राधिकारी" का गठन। 	<ul style="list-style-type: none"> पाठशाला जाने वाले बच्चों के लिए 'स्वास्थ्य कार्ड' की योजना शुरू करना जिसमें संबंधित बच्चे की संपूर्ण आवश्यक जानकारी होगी।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<ul style="list-style-type: none"> कृषि को प्रोत्साहन, जैविक उर्वरकों को कराधान से छूट। अक्षय रूप में बिहार पथ विकास निधि स्थापित करना जिसमें योजना, योजनेतर और अन्य स्रोतों से आय आएगी। 	<ul style="list-style-type: none"> पथ विकास के लिए 'स्वायत्त पथ प्राधिकरण' का गठन। विवादों के निपटान के लिए 'पंचाट' की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर मध्यवर्ती न्यायाधिकरण की शुरुआत। पटना में उच्च स्तरीय मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था का गठन। पटना में कीटनाशक अन्वेषण प्रयोगशाला की स्थापना। 	<ul style="list-style-type: none"> चुनिंदा आइटीआइ का पीपीपी आधार पर प्रबंधन। किसानों को 'भू-स्थिति कार्ड' का वितरण। सड़कों के उचित रखरखाव के लिए रखरखाव नीति बनाना। पीपीपी के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर बल देना जिसमें नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और पैथोलॉजी तथा रेडियोलॉजी प्रयोगशालाओं, अन्वेषण सेवाओं, अस्पतालों की सफाई, एंबुलेंस सेवा आदि का विकास जैसी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। पटना, मधेपुरा और बेतिया में तीन नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलना। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना। आर्यभट्ट तकनीकी विश्वविद्यालय की शुरुआत।
5. छत्तीसगढ़	<ul style="list-style-type: none"> कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए कृषि उपकरणों पर 25 प्रतिशत वितरण अनुदान। किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से दिए गए 'अल्पावधि कृषि ऋणों' पर ब्याज दर कम करके 6 प्रतिशत करना। 	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी व्यापारियों के लिए 'ई-विवरण' का प्रस्तुतीकरण बाध्यकारी बनाना। जिन किसानों को नैसर्गिक आपदाओं के कारण हानि हुई, उनके लिए 'खलिहान बीमा योजना' शुरू करना। सहकारी बैंकों के सुदृढीकरण के लिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें लागू करना। वृद्धिशील विनिर्माण उद्योगों को प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से 'विश्वकर्मा योजना' नामक नई योजना शुरू करना। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रमाणित बीजों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 'बीज बैंक' योजना की शुरुआत। मुख्य मंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना शुरू करना जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष कक्षा X वीं और XII वीं के अजा/अजजा के 1,000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए नई योजना शुरू करना। जनसंख्या और स्वास्थ्य योजना लागू करना। रायपुर में 100 बिस्तरों वाला कैसर अस्पताल बनाना और चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में 'आनुवंशिक बीमारी और आणविक जैविक प्रयोगशाला' की स्थापना। 'वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान' की स्थापना। होटल प्रबंधन संस्थान शुरू करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			<ul style="list-style-type: none"> रायगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना पारंपरिक हस्तकला क्षेत्र में प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए कला पाठशाला शुरू करना। रोजगार गारंटी योजना में कवर न हुए 5 जिलों के विकास के लिए 'मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना' शुरू करना। इसमें से 50 प्रतिशत का उपयोग बुनियादी सुविधा संबंधी कार्यों तथा शेष 50 प्रतिशत रोजगार उन्मुख कार्यों के लिए किया जाएगा। विकलांगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए क्षमता विकास की एक नई योजना शुरू करना। राज्य के महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों और जिला मार्गों के अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप उन्नयन की योजना शुरू करना।
6. गोवा	<ul style="list-style-type: none"> सुपारी की समर्थन मूल्य पात्रता विद्यमान 85 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति किलो करना। आरपीवीसी पाइपों के नेटवर्क वाली छिड़काव सिंचाई प्रणाली के लिए सब्सिडी को वर्तमान 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना। एचडीपीड पाइप नेटवर्क के लिए 25 प्रतिशत राज्य सब्सिडी की लागत की उच्चतम सीमा बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर करना। फसल कटाई यंत्र, प्रतिरोपक, झाड़ी कर्तक और धान थ्रेशर जैसे अन्य कृषि यंत्रों के क्रय के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी वृद्धि। किसानों के समूह को राज्य में नामित समितियों के माध्यम से उनके कृषि उत्पाद को जैविक के रूप में प्रमाणित करवाने के लिए वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत तक की सीमा के अनुसार 5 लाख रुपए की केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त 5 लाख रुपए की सब्सिडी देना। निरंतर आधार पर कूड़ा प्रबंधन के लिए उपयोग में लाने के लिए एक विशेष निधि बनाना। बिजली बिल के सकल मूल्य पर 	<ul style="list-style-type: none"> किफायत की दृष्टि से एसएचजी के प्रत्येक समूह में एकल कार्य को बढ़ावा देकर समूह दृष्टिकोण अपनाना। एसएचजी को उनके उत्पाद प्रत्येक तालुका में प्रदर्शित करने और बेचने के लिए प्रदर्शन और विपणन की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य योजना बनाना। कार्यरत महिलाओं के लिए पणजी और मार्गोवा में एक-एक होस्टल का निर्माण। राज्य को अगले दो वर्षों के भीतर कचरा-मुक्त करना। पणजी, मार्गोवा और मापुसा में पीपीपी फार्मेट में स्व निर्माण, परिचालन और अंतरण आधार पर समन्वित आधुनिक बस अड्डे का निर्माण। इन्फोग्राम योजना के तहत शेष 39 ग्राम पंचायतों के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू करना। नए पर्यटन वाहन खरीदने पर ऋण भुगतान स्थगन या पर्यटन वाहनों हेतु परमिट जारी 	<ul style="list-style-type: none"> नेत्रहीनों के लिए अलग आवासी पाठशाला खोलना जिसमें उन्हें ब्रेल लिपि सिखाने और विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण देने की सुविधा हो। भिन्न क्षमतायुक्त लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए विकलांग कर्मचारी के वेतन के आधार पर प्रोत्साहन राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करना। विकलांगों को सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत विभिन्न एनजीओ की सेवा उपलब्ध कराने वालों को प्रशिक्षित करना। सभी 'आंगनवाड़ी' केंद्रों के लिए प्रतिवर्ष लगभग 200 केंद्रों के अनुसार पांच वर्ष के भीतर नए परिसरों का निर्माण। 'आंगनवाड़ी' कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ देना। बिजली, उर्वरक और परिवहन क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए गोवा तक गैस पाइप डालने हेतु प्रयास करना

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<p>0.5 प्रतिशत का पर्यावरण-उपकर लगाना।</p> <ul style="list-style-type: none"> छोटे और बहुत छोटे किसानों की काजू और गन्ने की फसल के आकस्मिक अग्नि जोखिम के प्रति बीमा किस्त के 50 प्रतिशत की सब्सिडी देकर बीमा कवर उपलब्ध कराना। अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा कृषि विभाग से लिए गए ऋण की बकाया राशि माफ करना। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को उनके तुलनपत्र की स्थिति सुधारने तथा उनकी गतिविधियों के पुनरुज्जीवन के लिए सहायता देना। आवश्यक बुनियादी ढांचा और स्टाफ नियोजन ढांचा तैयार करके और सरकारी गजट में प्रवर्तन अधिसूचित करके 'गोवा सहकारी समिति अधिनियम, 2001' तथा 'गोवा सहकारी समिति नियमावली, 2003' लागू करना। अजा/अजजा के लोगों को उनके घरों के निर्माण और दुरुस्ती के लिए तथा भिन्न क्षमतायुक्त लोगों को स्व रोजगार के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए गए ऋण की बकाया राशि माफ करना। प्लास्टिक को व्यवस्थित रूप से संगृहीत करने तथा उसकी श्रेडिंग के लिए पंचायतों को अनुदान देना ताकि उसे सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जा सके। रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए उपयुक्त पैकेज बनाना। पिछड़ी तालुकाओं में वातावरण के अनुकूल और व्यवहार्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन तंत्र बनाना। राज्य में नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने और विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए नई इकाइयों तथा साथ ही मशीनरी तथा उपस्कर के विस्तार में 	<p>करने की अवधि एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2008 तक बढ़ाना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2007-08 के दौरान सिंचाई क्षमतायुक्त 5000 हेक्टेयर भूमि तैयार करना। 4.53 मिलियन क्यूबिक मीटर जल बढ़ाने के लिए गंजम में मांडेई नदी को ओपा में खांडेपार नदी से जोड़ने की परियोजना शुरू करना। गोवा विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए अध्ययन केंद्र का अलग विभाग खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<p>कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक निवेश करने वाली विद्यमान इकाइयों के लिए भी मशीनरी और उपस्कर पर प्रवेश कर में छूट देना।</p> <ul style="list-style-type: none"> • प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत वाले ग्राहकों की बिजली की कुल खपत पर 0.5 प्रतिशत ऊर्जा उप कर लगाना। • आईटी उत्पादों की अंतर-राज्यीय बिक्री पर कर की दर आधे प्रतिशत से घटाकर 'शून्य' प्रतिशत करना। 		
7. गुजरात	<ul style="list-style-type: none"> • ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन और अति निर्धन लोगों को राहत पहुंचाने और ऐसे क्षेत्रों में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों, मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं तथा छात्रावासों के लिए बिजली प्रभार की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना। • शहरी क्षेत्रों में आवासों और मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा 40 यूनिट से अधिक की बिजली की खपत के लिए बिजली प्रभार की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना। • अवशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना। • मनोरंजन और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हॉल, प्रेक्षकगृह, सिनेमागृह और होटल तथा रेस्तरा पर लागू बिजली प्रभार की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना। • विद्यमान 67 कर दरों को घटाकर मात्र 18 करके मोटर वाहन कर ढांचे को पुनर्निर्धारित करना। • विलासिता कर की दर में कटौती। 	<ul style="list-style-type: none"> • सहभागी सिंचाई प्रबंधन के अंतर्गत एक लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र और कवर करना। इस व्यवस्था के अंतर्गत जलप्रयोग से जुड़ी संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं को सिंचाई सुविधाओं का प्रबंधन सौंपा गया है। • 3 वर्ष से कम आयु वाले दस लाख बच्चों को आंगनवाड़ियों के माध्यम से पोषक आहार उपलब्ध कराने के लिए 'बाल भोग' योजना शुरू करना। • प्रायोगिक आधार पर दो महानगरों में महिला रोजगार कार्यालय खोलना। 	<ul style="list-style-type: none"> • आदिवासी विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज तैयार करना। • टपकन और छिड़काव सिंचाई जैसी लघु सिंचाई के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र कवर करना। • 4,500 स्थानों की क्षमता वाले 10 नए आईटीआई खोलना। • 2,695 अतिरिक्त 'आंगनवाड़ियां' खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
8. हरियाणा	<ul style="list-style-type: none"> कृषि को प्राप्त सभी अप्रत्यक्ष सब्सिडियों की पहचान करके ऐसी सभी सब्सिडियां किसानों को सीधे ही देने की पद्धति ढूंढना। राज्य में बिजली बचत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ विमर्श करके कॉम्पैक्ट फ्लूरसंट लैम्प्स और बिजली बचत के अन्य उपकरणों पर कर राहत प्रदान करना। यात्रियों द्वारा देय कुल किराए में परिवर्तन किए बिना यात्री कर घटाकर 25 प्रतिशत करना और आनुपातिक रूप में आधार किराया बढ़ाना। बैंकेट हॉल/लॉन और विवाह के भवनों पर उप कर। 	<ul style="list-style-type: none"> हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण स्थापित करना जो गांवों तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में बेहतर आवासी सुविधाओं तथा नागरी बुनियादी सुविधाओं की योजना और विकास संबंधी कार्य करेगा। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत पहचान किए गए फरीदाबाद कस्बे में बुनियादी सुविधाओं के मुख्य कार्य करना। सभी आधुनिक सुविधा युक्त क्रीडा अकादमी का गठन करना। संस्था-उद्योग सहभागिता की स्थापना, शेष संस्थाओं में संस्था प्रबंधन समिति का चरणबद्ध रूप से गठन। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मोबाइल फोन और कंप्यूटर दुरुस्ती, नेटवर्किंग, स्व-विकास, खुदरा कार्य आदि जैसे नए उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए “अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु कौशल प्रशिक्षण” नामक नई योजना शुरू करना। 	<ul style="list-style-type: none"> नाबार्ड और एनसीआर योजना बोर्ड की सहायता से 1,100 गांवों में जलापूर्ति बढ़ाकर प्रति दिन 70 लीटर करने का कार्य प्रारंभ करना। राज्य के छह कस्बों में गंदे पानी से संबंधित संयंत्रों का कार्य प्रारंभ करना। कक्षा छह से बारह तक के विद्यार्थियों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दृष्टि से इडीयूसएटी एजूसेट कवरेज प्राथमिक पाठशालाओं, कला उच्च माध्यमिक पाठशालाओं और तकनीकी संस्थाओं तक बढ़ाना। प्रत्येक खंड में 40 लाख रुपए की लागत का ग्रामीण स्टेडियम बनाना।
9. हिमाचल प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> वृद्धावस्था, विधवा और शारीरिक अक्षमता पेंशन योजना में 25,000 नए पेंशनभोगी जोड़ना। विशिष्ट से यथामूल्य उत्पाद शुल्क ढांचा अपनाने की संभावना खोजना और वैट कार्यान्वयन का आकलन करना। बिजली शुल्कों के लिए यथामूल्य प्रणाली अपनाने सहित कर वृद्धि करने हेतु अन्य क्षेत्रों की पहचान के लिए अध्ययन शुरू करना। संपत्ति लेनदेन में अपवंचन और कम मूल्यन रोकने की दृष्टि से भूमि बिक्री लेनदेन के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। 	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक जिलों को कवर करना। पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करना तथा पहले कदम के रूप में उनके दायित्वों के अनुरूप उन्हें भुगतान का प्रस्ताव देना। 	<ul style="list-style-type: none"> मंडी में सरकारी क्षेत्र का चिकित्सा महाविद्यालय और हमीरपुर में निजी क्षेत्र में चिकित्सा महाविद्यालय खोलना। 5 महाविद्यालय, 150 उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं, 50 उच्च माध्यमिक पाठशालाएं और 200 माध्यमिक पाठशालाएं खोलना। बागवानी उत्पादकता में तेजी लाने के लिए बागवानी पौधे तथा जड़ों का स्टॉक आयात करना। निजी कंपनियों द्वारा शीतगृहों की स्थापना के लिए पीपीपी को सहयोग जारी रखना ताकि किसान खाद्य की आधुनिक खुदरा दुकानों के माध्यम से अपने उत्पादों की मार्केटिंग सीधे ही कर सकें।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<ul style="list-style-type: none"> • ट्रैफिक जाम और प्रदूषण पर रोक के लिए वाहनों पर टोकन कर बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना। • 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक मूल निधि के साथ निर्धारित पेंशन निधि की शुरुआत करना जिसे प्रति वर्ष उचित रूप से बढ़ाया जाएगा ताकि समय पर यह पेंशन अपेक्षा का परिव्यय पूरा कर पाएगी। 		<ul style="list-style-type: none"> • सड़कों से न जुड़ी हुई सभी पंचायतों को मार्च 2008 तक और 500 से अधिक जनसंख्या वाली सभी बस्तियों को मार्च 2009 तक सड़कों से जोड़ना। • पेय जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हाइड्रोलॉजी परियोजना कार्यान्वित करना।
10. जम्मू और कश्मीर	<ul style="list-style-type: none"> • चार सदस्यीय मंत्री समिति का गठन करना जो करेतर राजस्व संग्रह की तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी और राजस्व प्रवाह वृद्धि की कार्यनीति पर ध्यान देगी। • सरकारी विभागों और नगरपालिका निकायों तथा निजी संस्थाओं द्वारा देय बिजली प्रभारों और जल प्रभारों के बकाया की वसूली के प्रयास गहन करना। • चुंगी कर संग्रह के लिए बुनियादी सुविधा सुधारना। • सामान्य बिक्री कर के अंतर्गत देय बकाया कर की स्वैच्छिक चुकौती के लिए अंतिम अवसर देने की दृष्टि से व्यापार और उद्योगों के लिए माफी योजना लाना। • पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत निपटान न हो पाए कर निर्धारण के ढेर सारे मामलों के निपटान के लिए जम्मू और कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 'मांग कर निर्धारण' की योजना लाना। • बेहतर कर संग्रह के लिए महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने वाले लोगों को ईनाम देने की योजना बनाना। • कूरियर सेवा, कोचिंग संस्थाएं, बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं आदि जैसी अन्य सेवाओं को भी कराधान की परिधि में लाना। • सेवाओं पर कर की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • उद्योगों को प्राप्त छूट को व्यवस्थित करने के मामले पर ध्यान देने के लिए समिति का गठन करना। • रोजगार से संबंधित मामलों पर ध्यान देने और प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों और संबंधित संस्थाओं के बीच समन्वय का दायित्व लेने के लिए उच्च अधिकारयुक्त रोजगार मिशन की स्थापना करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत नवोन्मेषी स्व-रोजगार परियोजनाओं के अवसर तलाशना। • उद्योग और वाणिज्य विभाग व्यापार नीति बनाएंगे जो विशेषतः नियंत्रण रेखा के पार व्यापार की मजबूत और अनुकूल संभावनाओं के संदर्भ में भावी मार्ग दिखाएंगे। • बिजली क्षेत्र में सुधार और उसकी पुनर्रचना के कदम उठाना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<ul style="list-style-type: none"> यात्रा और टैक्सी परिचालकों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं के प्रति कम ब्याज वाले ऋण। राज्य वित्त निगम द्वारा दिए गए गैर निष्पादक ऋणों के एक बारगी निपटान की योजना लाना। 		
11. झारखंड	<ul style="list-style-type: none"> संसाधन वृद्धि और राजकोषीय प्रबंधन में मजबूती लाने के उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। कर संग्रह प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए नौ स्थानों पर समन्वित चुंगी चौकियां स्थापित करना। सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए झारखंड सड़क विकास निधि स्थापित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> राज्य में सड़कों के विकास और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य के प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए झारखंड राज्य महामार्ग प्राधिकरण स्थापित करना। भारत सरकार के एनसीइआरटी की तर्ज पर शिक्षा प्रणाली के संगठन और प्रबंधन के लिए एससीइआरटी की स्थापना। गरीबी रेखा से नीचे के और इंदिरा आवास योजना का लाभ न मिले लोगों के लिए सीधा-कान्हो आवास योजना नामक नई योजना शुरू करना। सार्वजनिक वितरण की दुकानों संबंधी विवादों के निपटान के लिए सार्वजनिक वितरण शिकायत निवारण आयोग का गठन करना। 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि की नई तकनीक और साधनों की जानकारी के प्रसार को सुगम बनाने के लिए छत्रा और दुमका जिलों में कृषि पार्क बनाना। गोडा जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलना। कोलहान प्रभाग के शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलना। रामगढ़, चाइबासा और दुमका जिलों में एक-एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना। पीपीपी आधार पर अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ संस्थाएं खोलना। ग्रामीण जनता के लिए कंप्यूटर शिक्षा सुगम बनाने की दृष्टि से सभी सरकारी पाठशालाओं में कक्षा 9 से 12 में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना।
12. कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> किसानों, बुनकरों और मछुआरों के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा जारी रखना और इसे 'स्त्री शक्ति' तथा अन्य स्व-सहायता समूहों तक बढ़ाना। 19 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बड़े और छोटे सिंचाई कार्यों में पूंजी कार्यों के लिए अधिक आबंटन करना। सहकारी संस्थाओं से अल्पावधि फसल ऋण लिए किसानों को एक बारगी राहत पहुंचाने के लिए ऋण माफी के लाभ उन तक बढ़ाना। बुनकरों और मछुआरों को 25,000 रुपए तक माफी देना। राज्य द्वारा नियुक्त पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना। 	<ul style="list-style-type: none"> एक स्थायी "कर्नाटक कृषि माल वायदा बाजार आयोग" की स्थापना को सहायता देना। क्षेत्रीय असंतुलनों पर ध्यान देने और डा. नन्जुन्दप्पा समिति की सिफारिशें लागू करने के लिए विकास की आठ वर्षीय विशेष योजना बनाना। पेंशन की सभी योजनाएं लागू करने के लिए नया सामाजिक सुरक्षा और पेंशन निदेशालय बनाना। "लघु ऋण" की नई योजना शुरू करना जिसके अंतर्गत अजा/अजजा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के कुशल/अकुशल लोगों को छोटे कारोबार करने में सहायता दी जाएगी। 	<ul style="list-style-type: none"> "कर्नाटक जैव ईंधन कार्यक्रम" को मिशन तरीके से शुरू करना। इस मिशन का पहला चरण सात वर्ष का होगा जिसमें 15 चुनिंदा तालुकाओं में कार्य किया जाएगा। उत्तर कर्नाटक में दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र दुग्ध व्यवसाय विकास कार्यक्रम बनाना। अज तथा अजजा के लिए क्रमशः 25 और 5 मोरारजी देसाई आवासीय पाठशालाएं तथा 75 और 10 नए छात्रावास खोलना। पिछड़े वर्गों के लिए 22 नई मोरारजी देसाई निवासी पाठशालाएं और 75 नए छात्रावास खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<ul style="list-style-type: none"> “संध्या सुरक्षा” योजना के अंतर्गत कृषि श्रमिक, बुनकर, मछुआरे आदि सहित असंगठित क्षेत्र के छोटे और अत्यंत छोटे किसानों, श्रमिकों में से चुने गए 60 वर्ष से अधिक की आयु के नागरिकों को 400 रुपए प्रतिमाह की पेंशन देना। विधवाओं, वृद्धों और शारीरिक रूप से अपंग लोगों की मासिक पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करना। हक बीमा से समर्थित सभी संपत्तियों के लिए संपत्ति के पंजीयन के समय स्टॉप शुल्क के भुगतान पर 0.5 प्रतिशत रियायत देना। समाज तथा गरीब लोगों के हित में सभी प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबंध। 	<ul style="list-style-type: none"> “सुवर्ण सुरक्षा” योजना को केंद्र के 2007-08 के बजट में घोषित “आम आदमी बीमा योजना” के साथ जोड़ने की संभावना तलाशना। श्रम शक्ति के विभिन्न घटकों को कवर करते हुए “असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड” स्थापित करना। “कर्नाटक राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण” और “कर्नाटक राज्य विशेषज्ञ आकलन” समिति गठित करना। किसी विशिष्ट विकासक द्वारा घोषित संपूर्ण जानकारी के संग्रहण की दृष्टि से पीपीपी आधार पर “बंगलूर भू-विकासक, भवन निर्माता और आवास स्वामी रिपॉजिटरी” की स्थापना। 	<ul style="list-style-type: none"> रामनगरम सिटी को स्वास्थ्य-नगर के रूप में विकसित करना। चार पॉलीटेक्निकों का अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में उन्नयन तथा विश्वेशरैय्या प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा हसन में घटक अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना।
13. केरल	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी क्षेत्र से अन्य सभी मूल्यांकितियों को पिछले वर्ष कृषि आय कर में दी गई छूट को एक और वर्ष जारी रखना। नारियल पर कर छूट एक और वर्ष जारी रखना। सभी तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत कर लगाना जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित माल की सूची से तंबाकू को हटाने की अधिसूचना जारी होने पर लागू होगा। डिमैट लेनदेनों पर स्टाम्प शुल्क लगाना। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की हानि कम करने के लिए पैकेज लाना। 	<ul style="list-style-type: none"> सर्व शिक्षा अभियान के सहयोग से एक नई योजना शुरू करना। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए नई योजना शुरू करना। समग्र मूल्यांकन के बाद सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का समन्वयन करना। समाज कल्याण विभाग का नाम बदलकर कल्याण और महिला विकास विभाग रखना तथा इस विभाग के अंतर्गत परामर्शदाता समिति गठित करना। शहरी विकास के लिए केरल नगर विकास निगम स्थापित करना। कर्मचारी विकास, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के अद्यतन लेखे, बजट के नियम, लेखे, सार्वजनिक कार्य, स्टोर्स के लिए क्रय आदि जैसे प्रशासनिक सुधार लागू करने को प्राथमिकता देने के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाएं। 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि की वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर धान उत्पादन बढ़ाने के लिए पैकेज, वैज्ञानिक पद्धति अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर ऋण और धान उत्पादकों के लिए सहायक रोजगार सुनिश्चित करने की विशेष योजना। पीत पर्ण रोग से प्रभावित सुपारी किसानों के लिए विशेष पैकेज। कृषि क्षेत्र में बाजार की मध्यस्थता पर बल देना। किसानों, कृषि श्रमिकों और स्वयंसेवकों की सहायता से वाटरशेड कार्यक्रमों को जन आंदोलन में बदलना। सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त तथा अन्य को कम दर पर इलाज देने के लिए समग्र स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम बनाना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		<ul style="list-style-type: none"> जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कोच्ची और तिरुवनंतपुरम शहरों का विकास। 	<ul style="list-style-type: none"> नम भूमि क्षेत्रों का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण क्षेत्र में योजना बनाना। जैविक भिन्नता संरक्षण, पर्यावरणीय पर्यटन और राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्य की सुरक्षा के उपाय करना। स्थानीय शासन संस्थाओं की सहभागिता के साथ 'अक्षय परियोजना' नामक आइटी क्षेत्र परियोजना को पुनर्गठित करना। बायो-डीजल के रूप में रबड़ बीज के तेल का उपयोग, बायो-मेथिनेशन के माध्यम से नारियल के गूदे से गैस उत्पादन, गैसहाल उत्पादन की व्यवहार्यता की खोज जैसे ऊर्जा के अपारंपरिक कार्य शुरू करना। एनसीइआरटी और विदेशी भाषा प्रणाली संस्था की सहायता से निर्मित योजना द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का स्तर सुधारना।
14. मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से 7 प्रतिशत की दर पर सब्सिडी युक्त कृषि ऋण देना। विभिन्न विकास योजनाओं में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता और उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए 'जेंडर बजट' शुरू करना। वित्तीय प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक टेंडर प्रणाली शुरू करना। 	<ul style="list-style-type: none"> किसानों के कल्याणार्थ उपाय सुझाने के लिए 'किसान आयोग' की स्थापना। इंदिरा आवास योजना के लाभ प्राप्त न हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के लिए 'अपना घर' नामक नई योजना शुरू करना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े स्व-सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए महासंघ बनाना ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके तथा इन समूहों को बेहतर मार्केटिंग सुविधा मिल सके। लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर शैक्षिक और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना शुरू करना। 	<ul style="list-style-type: none"> एडीबी और अन्य वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से 27 राज्य महामार्गों और चार प्रमुख जिला सड़कों का विकास। पीपीपी के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के विकास पर बल देना। परेषण में होने वाली हानियों के स्तर को कम करने की दृष्टि से बिजली परेषण और वितरण प्रणाली का उन्नयन करना। नए पशु औषधालय और रीवा में पशु महाविद्यालय की स्थापना तथा पशु अस्पतालों का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण। विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पिछड़े वर्गों के मेधावी छात्रों को सक्षम बनाने के लिए छात्रवृत्ति शुरू करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		<ul style="list-style-type: none"> • 'बुदेलखंड विकास प्राधिकरण' की स्थापना करना जो इस पिछड़े क्षेत्र की विशिष्ट स्थिति के अनुसार विकास की रणनीति बनाएगा। • सुधार प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भोपाल में उत्तम संचालन केंद्र बनाना। 	<ul style="list-style-type: none"> • केंद्र सरकार के सहयोग से पांच पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोलना।
15. महाराष्ट्र	<ul style="list-style-type: none"> • विदर्भ के छह जिलों में किसानों को राहत देने के लिए सहायता का पैकेज जारी रखना। • तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत की दर पर कर लगाना। बीड़ी और गैर विनिर्मित तंबाकू पर छूट देना। • राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत छोटे और बहुत छोटे किसानों को प्रीमियम सब्सिडी देना। • पर्यटन परियोजनाओं के स्थान के आधार पर विलासिता कर, मनोरंजन कर और स्टाम्प शुल्क के भुगतान में रियायत देकर पर्यटन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना। 		<ul style="list-style-type: none"> • सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8,528 कक्षाओं के कमरों, 19 खंड संसाधन केंद्रों और 1,073 समूह संसाधन केंद्रों का निर्माण। • पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक छात्रवृत्ति की दर बढ़ाना। • उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम सिंचाई संभावना के लिए अंतिम स्थलीय परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देना। • महाराष्ट्र स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट लागू करना जिसके अंतर्गत 35 जिले मंत्रालय से जोड़े जाएंगे और सभी तालुकाओं को जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाएगा। • उपलब्ध बिजली के उचित उपयोग की दृष्टि से बिजली आपूर्ति बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण के लिए उपाय करना। • चिकित्सा शिक्षा और रुग्ण देखभाल में आधुनिक स्तर प्राप्त करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों का उन्नयन। • वन और पेड़ों की संख्या बढ़ाने तथा वन क्षेत्र में पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाएं बनाना। • विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम कम करने की परियोजना कार्यान्वित करना जिससे राज्य के तटीय जिलों को लाभ मिलेगा। • भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत पेय जल की समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बस्तियों को कवर करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
16. मणिपुर			<ul style="list-style-type: none"> गैर-सहायता प्राप्त और स्थायी रूप से गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शुल्क की प्रतिपूर्ति करना। माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की दर बढ़ाना। एनएलपीसीआर के अंतर्गत 50 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाकर पहाड़ों तथा जिरिबाम में 4 जिला अस्पतालों का उन्नयन करना। मारम से इंफाल तक की 78 कि.मी. की सड़क का उन्नयन करके उसे चार मार्ग वाला बनाना तथा खोउपुम होकर बिष्णुपुर से रेंगपांड के 93 कि.मी. के वाहनयोग्य पुराने कचर मार्ग को ठीक करना।
17. मेघालय		<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय बांस मिशन की सहायता से राज्य बांस नीति कार्यान्वित करने के लिए राज्य बांस विकास एजेंसी स्थापित करना। 	<ul style="list-style-type: none"> लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 1800 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करना। वर्षा जल संचय और भू-जल संभावना की खोज करना। ड्राइविंग लाइसेंस, उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट्स में स्मार्ट कार्ड लागू करना और परमिट निर्गम सुगम बनाने की दृष्टि से कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया में उन्नयन करना। कवर न हुई और आंशिक रूप से कवर हुई 800 बस्तियों, 1000 ग्रामीण पाठशालाओं और 50 आइसीडीसी केंद्रों को केंद्रीय क्षेत्र के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कवर करना। 2530 हेक्टेयर कवर करते हुए भू-सुधार, वनीकरण और जल वितरण का कार्य करना, भूक्षरण नियंत्रण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त 680 हेक्टेयर भूमि लाना और 250 जल संचय फार्म / तालाब बनाना। केंद्रीय क्षेत्र मिल गेट मूल्य योजना, हथकरघा समूह विकास कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			<ul style="list-style-type: none"> न्यू शिलांग में आइटी एस्टेट और सामान्य सेवा केंद्रों, एसडब्ल्यूएएन, एनइजीपी के अंतर्गत डाटा केंद्र बनाना।
18. मिजोरम	<ul style="list-style-type: none"> गारंटी शोधन निधि के गठन को अंतिम रूप देना। अधिक क्षेत्रों को कवर करते हुए वैट की लेखापरीक्षा/आकलन की प्रक्रिया जारी रखना। सड़कों और पुलों पर पथ कर तथा लघु सिंचाई पर जल उपकर लगाना। 		<ul style="list-style-type: none"> “बांस विकास और अकाल का सामना करने की योजना” को प्राथमिकता देना जारी रखना। एजवाल सिटी के शहरी विकास के लिए “उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास परियोजना (चरण 1)” शुरू करना।
19. नागालैंड		<ul style="list-style-type: none"> “किसान वर्ष” कार्यक्रम को 2007-08 तक बढ़ाना जिसमें विपुल संसाधनों को उपयोग में लाने पर ध्यान केंद्रित करना ताकि न केवल आत्मनिर्भरता बल्कि निर्यात हेतु अधिशेष की स्थिति पर पहुंचा जा सके। 	<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नागा अस्पताल प्राधिकरण, कोहिमा के साथ जुड़े नर्सिंग कॉलेज को शुरू करना। नवनिर्मित जिलों में तीन नए जिला अस्पताल खोलना। एडीबी के ऋण से कोहिमा के लिए गंदे पानी का निकास और स्वच्छता प्रणाली स्थापित करना। आइसीएफएआई विश्वविद्यालय के तत्वावधान में व्यवसाय प्रशासन, कंप्यूटर प्रयोज्यता, विज्ञान, आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों के स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करना।
20. उड़ीसा	<ul style="list-style-type: none"> लिफ्ट सिंचाई योजना को फ्री जलापूर्ति जारी रखना। 	<ul style="list-style-type: none"> बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना लागू करना। 300 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बिजली मुहैया कराने के लिए “बिजू ग्राम ज्योति” नामक नई योजना लागू करना। 	<ul style="list-style-type: none"> बिजू पटनाईक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत घटक महाविद्यालयों में बुनियादी सुविधा विकास करना। “गहन खनिज अन्वेषण और खनिज संसाधनों का आकलन” नामक नई योजना शुरू करना।
21. पंजाब	<ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बुनियादी सुविधा तथा नागरी सेवाओं में सुधार के लिए उनकी सहायता के लिए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अंतरण करना। आधारभूत स्टाम्प शुल्क दर 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। 	<ul style="list-style-type: none"> 1.9.2007 से सभी सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए 2 लाख रुपए वार्षिक तक के चिकित्सा बीमा की ‘भाई धनइया सेहत सेवा योजना’ लागू करना। यह पूर्ववर्ती उस योजना का विस्तारित रूप है जो प्राथमिक कृषि समितियों के सदस्यों तक ही सीमित थी। ऐसी ही योजना बीपीएल परिवारों के लिए भी 	<ul style="list-style-type: none"> भूमि की गुणवत्ता घटने और जल बहाव की समस्या के समाधान के लिए शून्य जुताई, गहरी जुताई, रेज्ड बेड प्लांटिंग, लेजर भू-समतलीकरण आदि जैसी संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का कार्यक्रम लोकप्रिय करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		शुरू करना। इसमें प्रत्येक परिवार 100 रुपए वार्षिक का प्रीमियम अदा करेगा और शेष प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाएगा।	<ul style="list-style-type: none"> कृषि-प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने संबंधी विधान अधिनियमित करना और सब्जी, खाद्यान्न तथा दुग्ध व्यवसाय में ठेका कृषि तथा खुदरा कार्य को संगठित करने को बढ़ावा देना। उत्पादकता और वृद्धि तथा समष्टि प्रबंधन कार्य योजना के लिए पंजाब में कृषि उत्पादन पैटर्न समायोजन कार्यक्रम के माध्यम से विविधीकरण के लिए प्रायोगिक परियोजना बनाना। बागवानी पर विशेष बल देना। प्रयोगशालाओं और फार्मों के बीच की दूरी मिटाने के लिए राज्य में 20 किसान प्रशिक्षण केंद्र खोलना। घाटे में चल रहे दूध संगठनों के पुनरुज्जीवन का प्रस्ताव।
22. राजस्थान	<ul style="list-style-type: none"> स्व-सहायता समूहों का हस्तनिर्मित माल करमुक्त करना। बैंकेट हॉल, विवाह और पार्टी स्थलों पर विलासिता कर लगाना। जयपुर में शुरू की गई 'कहीं भी पंजीयन' सुविधा शेष राजस्थान तक बढ़ाना। सरकारी कर्मचारियों की सीपीएफ योजना की तर्ज पर असंगठित श्रमिकों के लिए 'विश्वकर्मा' नामक नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू करना। 	<ul style="list-style-type: none"> 'राजस्थान सोशल सेक्टर वाएबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम' शुरू करना। 3 करोड़ रुपए की मूल निधि के साथ 'राजस्थान इन्नोवेशन फाउंडेशन' की स्थापना करना। नया उपभोक्ता कार्य निदेशालय स्थापित करना। आर्थिक रूप से दुर्बल घटकों की पहचान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'आर्थिक रूप से दुर्बल घटक आयोग' की स्थापना करना। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक जिले में चल कम्प्यूटर शिक्षा जिसमें बस और कम्प्यूटरों की लागत का 75 प्रतिशत भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 1,500 उच्च प्राथमिक पाठशालाओं का माध्यमिक पाठशालाओं में तथा 600 माध्यमिक पाठशालाओं का उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में उन्नयन। एक नया अभिघात (ट्राउमा) अस्पताल खोलना। मानसरोवर में एक नया अस्पताल खोलना जिसका प्रबंधन बॉम्बे हास्पिटल जैसे किसी सुस्थापित अस्पताल की भागीदारी से किया जाएगा। ग्रामीण और विरासती पर्यटन को कवर करने के लिए होटल नीति में संशोधन करना। 1500 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलना। संक्रमणीय बीमारियों की रोकथाम करने तथा शीघ्र निदान और उपचार के लिए पतंजलि आरोग्य योजना शुरू करना। पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय पर्यटन नीति बनाना।
23. सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करना। 	<ul style="list-style-type: none"> महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आय, रोजगार और सामाजिक-राजनैतिक सहभागिता संबंधी मामलों के अध्ययन 	<ul style="list-style-type: none"> बीज उत्पादन पर विशेष बल देना जिसमें बीज की जांच और प्रमाणन के लिए सहायक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<ul style="list-style-type: none"> सिक्किम में महिला तथा बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत सर्वोत्तम एनजीओ को पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहन देना। प्रसिद्ध निजी पार्टियों द्वारा तकनीकी संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थाओं और प्रबंधन स्कूलों में निवेश करने को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं तक सुगम पहुंच और कर में रियायत देना। 	<ul style="list-style-type: none"> और जांच के लिए राज्य नैदानिक विशेषज्ञ समिति स्थापित करना। जैव-प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर समग्र नीति बनाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना। एक स्वयंपूर्ण क्षमता निर्माण निदेशालय की स्थापना करना जिसमें विशेषज्ञ और व्यावसायिक व्यक्ति सहभागी किए जाएंगे। प्रत्येक विभाग उनके संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए उनके वार्षिक व्यय का कम से कम 2 प्रतिशत का विनिधान करेगा। पंचायती राज संस्थाएं भी उनके कुल निधि विनिधान का 2 प्रतिशत क्षमता निर्माण कार्यों के लिए ही अलग रखेंगी। क्षमता निर्माण निदेशालय द्वारा राज्य में विदेशी भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए निधि परिचालित की जाएगी। राज्य में हरियाली बढ़ाने की प्रक्रिया एक निर्धारित समय में तेज करने के लिए पर्यावरण और हरियाली मिशन की स्थापना करना। हिम नदियों की स्थिति तथा सिक्किम में जल प्रणाली पर उसके प्रभाव के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ दल का गठन करना। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों का एक साथ विकास करने तथा विकास का अंतर मिटाने की दृष्टि से ‘‘सिटी-स्टेट इनिशिएटिव’’ नामक नई परियोजना संबंधी विधायी कार्रवाई शुरू करना। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ध्यान देने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग में तीन अलग निदेशालयों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और सुसंगतीकरण। शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करने, शिक्षा से संबंधित सभी संस्थाओं का 	<ul style="list-style-type: none"> लोक और पारंपरिक औषधि चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान अनुदान देना। बागवानी तथा पुष्प-कृषि को बड़े कार्यक्रम की हैसियत देना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
		<p>पर्यवेक्षण करने और उच्च शिक्षा नीति के व्यापक प्रभाव पर ध्यान देने के लिए राज्य स्तरीय शिक्षा विनियामक आयोग स्थापित करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ज्ञान, शिक्षा देने का कौशल बढ़ाने, शिक्षा का ढांचा और शैक्षिक तकनीक के उन्नयन के लिए राज्य से शिक्षकों को राज्य के बाहर की संस्थाओं में भेजने और साथ ही अन्य राज्यों के ख्यातनाम शिक्षकों और शिक्षाविदों को सिविकम में बुलाने के लिए अध्यापन कौशल कोष नामक नया कार्यक्रम शुरू करना। • सभी जिला मुख्यालयों में आधारभूत संप्रेषण सुविधाओं से युक्त मीडिया केंद्र बनाना। • भारत और विदेश दोनों से लघु और मझौले उद्यमों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करना। 	
24. तमिलनाडु	<ul style="list-style-type: none"> • सहकारी फसल ऋण पर ब्याज दर 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना। फार्म सिंचाई संबंधी बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से प्राथमिक सहकारी कृषि समितियों और ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से 100 करोड़ रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। • फसल बीमा के लिए किसानों को वित्तीय सहायता। • अंतरण की राशि राज्यों के स्वयं के कर राजस्व के 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत करना। • 60 वर्ष से अधिक आयु के हथकरघा बुनकरों की मासिक पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए करना। • दो चरणों में ई-टेंडरिंग लागू करना। 1.7.2007 से शुरू होने वाले पहले चरण में 10 लाख रु. से अधिक मूल्य के टेंडर खोलने के लिए टेंडर फार्म इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं और 1.10.2007 से शुरू हो रहे दूसरे चरण 	<ul style="list-style-type: none"> • अनुपयोगी भूमि सुधार की योजना जारी रखना तथा उसे निर्धन कृषक परिवारों को निःशुल्क वितरित करना। • दक्षिणी जिलों में नए उद्योग लगाने को बढ़ावा देने की दृष्टि से विरुधुनगर जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करना। • 25,000 नए स्व सहायता समूह बनाना तथा उनकी क्षमता निर्माण के लिए और उन्हें आय उत्पादक कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता देना। • निर्धनों में भी निर्धन, निर्धन महिलाएं, विकलांग और निराश्रितों जैसे समाज के अति निर्धन घटकों के कल्याण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 15 जिलों में 15 पंचायत यूनियनों में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त 'वजंदू कट्टुवोम' परियोजना का पहला चरण लागू करना। • सरकार के माध्यम से 50,000 बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देना। • सरकार की मुख्य कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य 	<ul style="list-style-type: none"> • जल के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1,30,100 एकड़ भूमि पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ लघु सिंचाई तकनीक शुरू करना। • सभी जिलों में प्रदर्शन के माध्यम से सूक्ष्म फार्मिंग शुरू करके कृषि की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना। • नदी का उर्वर क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से विश्व बैंक की सहायता से समन्वित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार तथा प्रबंधन परियोजना शुरू करना। • 100 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च विद्यालयों में तथा 80 उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नीत करना। • सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करना। • सरकारी कला तथा विज्ञान माहविद्यालयों में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे सभी छात्रों को शिक्षा शुल्क से

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्र
	में संबंधित विभाग की वेबसाइटों के माध्यम से भी बिड प्रस्तुत किये जा सकते हैं।	स्तरीय उच्च स्तर की निगरानी समिति का गठन करना।	<p>छूट प्रदान करना जिससे सरकारी महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा मुफ्त मिल सके।</p> <ul style="list-style-type: none"> • पेरम्बलुर जिले में दो नई सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं (आइटीआइ) और शिवगंगा जिले में एक नई आइटीआइ खोलना। • दक्षिणी जिलों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार करने की दृष्टि से तिरुनेलवेली अण्णा विश्वविद्यालय नामक एक नया तकनीकी विश्वविद्यालय खोलना। • तिरुवरूर और धर्मापुरी में दो नए चिकित्सा महाविद्यालय। • नीलगौरि जिले में चाय बागानों के पुनरुज्जीवन तथा सहकारी चाय कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार के चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से योजना लागू करना। • परिवहन की समस्याओं को दूर करने के लिए चेन्नई शहर में मेट्रो रेल परियोजना लागू करना। • 9,000 ग्रामीण बस्तियों में पर्याप्त सुरक्षित जलापूर्ति की योजना बनाना। • जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत चेन्नई शहर में टोस अनुपयोगी माल प्रबंधन प्रणाली सुधारने तथा जलापूर्ति बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने की योजना लागू करना।
25. त्रिपुरा	<ul style="list-style-type: none"> • गारंटी शोधन निधि शुरू करना। • जन सेवाओं में सुधार करने और कर संग्रह में और वृद्धि करने की दृष्टि से कर ढांचे को मजबूत बनाना। • स्व-सहायता समूहों को उनके निष्पादन के आकलन के आधार पर पूंजी सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 2 करोड़ रुपए के प्रारंभिक अंशदान से एक मूल निधि का निर्माण करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • पशु बीमा योजना का सभी जिलों तक विस्तार करना, दुग्ध विपणन प्रणाली को मजबूत बनाना और पशु चिकित्सा सेवा नेटवर्क का विस्तार करना। • बीपीएल परिवारों के लिए प्रायोगिक आधार पर बीमा योजना शुरू करने पर विचार करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • डिग्री और डिप्लोमा माइयूल्स वाली त्रिपुरा इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी खोलना। • कृषि क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिए कृषि महाविद्यालय खोलना। • फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण और प्रचार के माध्यम से आधुनिक प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देने जैसे कार्य करके बागवानी विकास पर बल देना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त आठ मॉडल एक्वा पंचायत, तीन झींगा गांवों तथा चार विशेष गांवों के विकास का कार्य शुरू करना। मत्स्य व्यवसाय में मल्टिपल स्टॉकिंग तथा हारवेस्टिंग की धारणा लाना। स्व-सहायता समूहों के गठन, जल निकाय निर्माण और रबर के अतिरिक्त पौधे लगाने के माध्यम से वन क्षेत्र के विकास पर बल देना। निश्चित सिंचाई के अंतर्गत 7550 हेक्टर क्षेत्र कवर करने का लक्ष्य। स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए बुराताली में निवासी शाला और कोरबूक में आश्रम शाला शुरू करना।
26. उत्तराखंड		<ul style="list-style-type: none"> आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 'आयुष ग्राम' की स्थापना। स्थानीय उत्पादकों द्वारा स्थानीय उत्पाद, माल औषधियां और हस्तनिर्मित माल को स्थानीय रूप से बेचने को प्रोत्साहित करने और उनके माल की मार्केटिंग को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से ग्रामीण कारोबार हब की स्थापना करना। राज्य में तेजी से समाप्त हो रहे जल स्रोतों को बचाने और पेय जल के संरक्षण की दृष्टि से 'राज्य स्तरीय जल संवर्धन मिशन' की स्थापना करना। 	<ul style="list-style-type: none"> टपकेश्वर के करीब पीपीपी आधार पर होटल/सम्मेलन केंद्र बनाना। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थलों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए पीपीपी आधार पर रोप वे का निर्माण करना। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी की सहायता से 31 शहरों में पेय जल व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, ठोस निपटान प्रबंधन और सड़क निर्माण जैसे कार्य करना। वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्रों में विशेष प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देना। राज्य में वैमानिकीय गतिविधियों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में तकनीकी कौशल प्राप्त करने तथा इस क्षेत्र की ओर उद्यमियों का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से वैमानिकी विश्वविद्यालय/ अकादमी स्थापित करना। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देहरादून में मानसिक स्वास्थ्य संस्था खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
27. उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> • वृद्धों, विकलांगों, निराश्रित महिलाओं और किसानों को देय पेंशन 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के पोषण और सुदृढ़ीकरण के लिए आंबेडकर गांवों के समन्वित विकास की दृष्टि से ‘‘डॉ. आंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना’’ नामक एक नई योजना शुरू करना। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण रोजगार निर्माण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। • शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शहरी निकायों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की दृष्टि से एक नई योजना बनाना। • पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ ‘‘समन्वित विकास योजना’’ शुरू करना। • जन सहयोग से पादरोपण करने और वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन’ नामक एक नई योजना शुरू करना। • 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करना। • नई चीनी उद्योग नीति बनाना। • सहकारी क्षेत्र और राज्य चीनी मिल निगम द्वारा चलाए जाने वाले और घाटे में चल रहे चीनी मिलों का निजीकरण करना। • प्रभावी व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से व्यावसायिक शिक्षा परिषद का गठन करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • निजी निवेशकों की सहायता से इलाहाबाद और अनापारा में दो पॉवर हाउस बनाना। • तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अभियांत्रिकी संस्था को भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलूर की तर्ज पर विकसित करना। अन्य अभियांत्रिकी संस्था का आइआईटी स्तर पर उन्नयन करना। • दो नए राज्य होमियोपैथी महाविद्यालय और दो नए एलोपैथी महाविद्यालय खोलना। • 813 नए प्राथमिक विद्यालय और 4,500 नए कनिष्ठ उच्च विद्यालय सुविधा रहित क्षेत्रों में खोलना। • व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड का गठन करना। • जिन विकास खंडों में अब तक स्नातक महाविद्यालय स्थापित नहीं हुए हैं, वहां निजी क्षेत्र के स्नातक महाविद्यालय खोलने को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता देना। • शहरी क्षेत्रों में 35 और ग्रामीण क्षेत्रों में 125 आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल और 92 नए सरकारी होमियोपैथी अस्पताल खोलना।
28. पश्चिम बंगाल	<ul style="list-style-type: none"> • भूमि वितरण के एक लाख लाभार्थियों और एक लाख रेकार्डेड शेयर-क्रॉपरों को कम ब्याज दर (4 प्रतिशत) पर बैंक ऋण मुहैया कराना। • भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए भविष्य निधि की योजना के अंतर्गत कवरेज 9.42 लाख से बढ़ाकर 10.50 लाख करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • असंगठित क्षेत्र के कामगारों की भविष्य निधि योजना के लाभार्थियों की संख्या लगभग 7.92 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करना। • पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अलावा बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 के और पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1954, जो अब निरस्त हो गए हैं, के अंतर्गत 30 	<ul style="list-style-type: none"> • 500 प्राथमिक विद्यालय, 750 शिशु शिक्षा केंद्र, 1000 कनिष्ठ उच्च विद्यालय और 100 कनिष्ठ मंदरसे खोलना। • 500 उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा 100 मंदरसों को उच्च मंदरसों में उन्नीत करना। • 500 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना। उत्तरी बंगाल, पश्चिमांचल और सुंदरबन क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक सरकारी

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<ul style="list-style-type: none"> कृषि मजदूरों की 'आम आदमी बीमा योजना' में सहभागी होना और इस योजना को कृषि मजदूरों की भविष्य निधि योजना से समन्वित करना। वाणिज्यिक कर निदेशालय का कंप्यूटरीकरण करना। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वाणिज्यिक कर आयोग की समिति की सिफारिशों के आधार पर वैट विवरणी को और सरल करना। पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग का योजना परिव्यय बढ़ाना। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, असमर्थता पेंशन, कारीगर पेंशन, कृषक पेंशन तथा महुआरा पेंशन की योजना के अंतर्गत व्याप्ति बढ़ाना। अपनी कुल बिक्री का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों के संदर्भ में आकलन पूर्व के चरण में निर्यात की गई मात्रा के संबंध में इनपुट टैक्स की वापसी करना जैसा कि 100 प्रतिशत निर्यात-मुख इकाइयों के संबंध में किया गया है। विवादित कर के 46 प्रतिशत और विवादित ब्याज तथा दंड के 5 प्रतिशत का भुगतान करने पर 30 जून 2007 तक के बिक्री कर संबंधी विवादों को निपटान योजना की प्रयोज्यता बढ़ाना। पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 में दिए गए बिक्री मूल्य की परिभाषा संशोधित करके सामान की सुपुर्दगी के समय या सुपुर्दगी से पहले प्रभारित की गई राशि बिक्री मूल्य से बाहर रखना। बंद पड़े चाय बागानों को पुनः खोलने और पुनःपादरोपण तथा मशीनरी में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कम ब्याज वाले ऋण तथा अतिरिक्त राहत देना। 	<p>जून 1997 तक पारित आकलन आदेशों के विरुद्ध अपील तथा संशोधन के लंबित मामलों का निपटान आयोग की परिधि में लाकर इस आयोग का क्षेत्र विस्तार करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> माइक्रो और लघु उद्योगों के सहायतार्थ प्रोत्साहन योजना शुरू करना। राज्य में जिले की स्थिति के आधार पर माइक्रो उद्योग निवेश के 35 प्रतिशत तक की पूंजी निवेश सब्सिडी की और लघु उद्योग इकाइयां निवेश के 20 प्रतिशत तक की पूंजी निवेश सब्सिडी की हकदार होंगी। व्यक्तिगत रूप से या स्व-सहायता समूह बनाकर लघु उद्योग उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले उन युवाओं को प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता देना जो रोजगार केंद्रों में पंजीकृत हैं। 	<p>माहविद्यालय और सरकारी सहायता प्राप्त दस और महाविद्यालय खोलना जहां सामान्य विषयों के अलावा प्रबंध शिक्षा और उच्च स्तरीय कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया जाएगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> उत्तर 24 परगना जिले में एक नया स्वयंपूर्व विश्वविद्यालय खोलना। सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना और राज्य से गुजरने वाली नदियों का सुधार कार्य करना। पुष्प कृषि और बागवानी पर विशेष बल देते हुए फसल विविधता को प्रोत्साहित करना। लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न जिलों में 45 औद्योगिक समूहों की स्थापना करना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (जारी)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
	<ul style="list-style-type: none"> तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत की दर पर मूल्यवर्धित कर लगाना। 		
29. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	<ul style="list-style-type: none"> पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से दिल्ली की सीमा के भीतर के चार सितारा तक के होटलों को अप्रैल 2007 और अक्टूबर 2010 के बीच कर अवकाश देना। कल्याण गृहों और अस्पतालों के कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा करना। आर्थिक रूप से दुर्बल और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों का मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करना। तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों पर 12.5 प्रतिशत कर लगाना। 	<ul style="list-style-type: none"> जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत भारत सरकार की वित्तीय सहायता से दुर्बल वर्ग के लिए बड़े पैमाने पर गृह निर्माण करना। बहु उद्देशीय सहकारी समितियों का गठन करके झोपड़पट्टी निवासियों को आवास उपलब्ध कराना। यमुना नदी विकास प्राधिकरण का गठन करना। महिला और बाल कल्याण की सभी योजनाओं तक पहुंच और उनका प्रभाव बढ़ाने की दृष्टि से उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए महिला और बाल विकास निदेशालय खोलना। 	<ul style="list-style-type: none"> बेहतर और संतुलित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिसंबर 2009 तक शहर के विभिन्न भागों में 53 भूमिगत जलाशय बनाना। उक्त 53 भूमिगत जलाशयों में से 13 का निर्माण पहले ही पूरा हो गया है और पांच का अधिकांश कार्य लगभग पूरा हो गया है। नियमित की गई अनधिकृत बस्तियों में सड़कें, नालियां, जलापूर्ति, सीवरेज, बगीचा, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा, आदि, जैसी सभी नागरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। दिल्ली के सभी गांवों की बस्तियों का गंदा जल यमुना नदी में मिलने से रोकने के लिए सीवरेज प्रणाली उपलब्ध कराना। दिल्ली की बिजली की मांग पूरी करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू करना। स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तर पर अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा मुहैया कराने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करना। आठ नए विद्यालय खोलना। सरकारी विद्यालयों के मेधावी छात्रों को स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से पांच विद्यमान विद्यालयों को प्रतिभा विकास विद्यालयों में परिवर्तित करना। कंप्यूटरयुक्त शिक्षा परियोजनाओं को 200 विद्यालयों से बढ़ाकर शेष सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तक पहुंचाना। सभी विद्यालय पुस्तकालयों का कंप्यूटरीकरण। बकोली में महात्मा गांधी ग्रामीण ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में 'आंबेडकर विश्वविद्यालय' नामक एक नया विश्वविद्यालय खोलना।

अनुबंध 1 : 2007-08 के राज्य बजटों की प्रमुख नीतिगत पहलें (समाप्त)

राज्य	राजकोषीय	संस्थागत	क्षेत्रीय
			<ul style="list-style-type: none"> आइटीआइ में सभी पाठ्यक्रमों के लिए कन्या विद्यार्थियों को शुल्क से छूट देना। बहु उपचार युक्त अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के अलावा रोकथाम, प्रोत्साहन, उपचार और परिवार कल्याण की सेवाओं सहित समग्र स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल देना। पारंपरिक फसलों के अलावा पुष्प कृषि और बागवानी जैसी नकदी फसलों की विविधता लाने को प्रोत्साहन देना। सभी प्रकार के वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मिशन को जारी रखना।
10. पुदुचेरी	<ul style="list-style-type: none"> मछली पकड़ने की नौका के स्वामी द्वारा बीमा कंपनी को भुगतान किए गए प्रीमियम पर सब्सिडी बढ़ाना। कृषि ऋण समिति/भूमि विकास बैंक को शेयर पूंजी सहायता देना। 	<ul style="list-style-type: none"> फसल बीमा का विस्तार कपास, मूंगफली और केले तक करना। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. द्वारा शुरू की गई 'वर्षा बीमा' नामक मौसमी वर्षा बीमा योजना लागू करना। दूध उत्पादकों के लाभार्थ किसान आय गारंटी योजना नामक एक नई योजना शुरू करना। रोजगार उत्पत्ति की दृष्टि से उन ग्रामीण और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देना जो मुख्यतः स्वामी द्वारा ही चलाए जाते हैं। रोजगार उन्मुख प्रदूषण रहित उद्योगों, आइटी, जैव प्रौद्योगिकी और ऐसे ही अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना। लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने की दृष्टि से ई-गवर्नेंस प्रथा अपनाना। पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन के भाग के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को कंप्यूटरीकृत करना। सभी क्षेत्रों में तेज और संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए आधारभूत आयोजना को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से जिला योजना समिति का गठन करना। 	<ul style="list-style-type: none"> कृषक समाज में आदर्श इकाई के रूप में कार्य करने के लिए सब्जी उत्पादन में सूक्ष्म कृषि पर एक नई योजना लागू करना। माहे जनरल अस्पताल के लिए ट्राउमा केयर सेंटर बनाना। पुदुचेरी टाउन क्षेत्र की तेजी से बढ़ रही बिजली की मांग पूरी करने की दृष्टि से वेंकट नगर में सब स्टेशन स्थापित करना। पुदुचेरी केंद्रीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को सभी सरकारी महाविद्यालयों और सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी सोसाइटी महाविद्यालयों में निःशुल्क उच्च शिक्षा देना। सरकारी महाविद्यालयों में बी.टेक. (कंप्यूटर विज्ञान), एमसीए और एमएससी (कंप्यूटर विज्ञान) का अध्ययन कर रहे बीपीएल परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त में कंप्यूटर देना। तेज औद्योगिक विकास की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता से औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट भाषण, 2007-08.